# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority


© Govt. of Haryana

No. 125-2024/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, AUGUST 14, 2024 (SRAVANA 23, 1946 SAKA)

**हरियाणा सरकार**

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 14 अगस्त, 2024

**संख्या 09/39/2024-4C-II.**—हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 84 की उप–धारा (1) के साथ पठित धारा 69 के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या का0आ0 86/ह0अ0 24/1973/धा0 69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में, तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

**संशोधन**

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या का0आ0 86/ह0अ0 24/1973/धा0 69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में, पैरा 3 में, उप–पैरा (ix) के बाद, निम्नलिखित उप–पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :–

''(x) 100% की छूट गौशालाओं को स्वीकार्य होगी। तथापि, यदि उसके किसी हिस्से का निर्माण या उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किया गया है, तो उस हिस्से के लिए सम्पत्ति कर, वाणिज्यिक दरों के अनुसार प्रभारित किया जाएगा।''

विकास गुप्ता,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

**Notification**

The 14th August, 2024

**No. 09/39/2024-4C-II.**— In exercise of the powers conferred under clause (a) of section 69 read with sub-section (1) of section 84 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 86/H.A.24/1973/S. 69/2013, dated the 11th October, 2013 with immediate effect, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 86/H.A.24/1973/S. 69/2013, dated the 11th October, 2013, in para 3, after sub-para (ix) the following sub-para shall be inserted, namely:-

"(x) A rebate of 100% shall be admissible to Gaushalas. However, if any portion thereof has been constructed or used for commercial purposes, the property tax for that portion shall be charged as per the commercial rates.".

VIKAS GUPTA,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

11241—C.S.—H.G.P., Pkl.